



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 106]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 27, 2018/चैत्र 6, 1940

No. 106]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 27, 2018/CHAITRA 6, 1940

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2018

विषय: चीन जनवादी गणराज्य से बसों या लारियों में प्रयोग किए जाने वाले न्यू न्यूमेटिक टायरों के आयातों से संबंधित प्रतिसंतुलनकारी शुल्क/सब्सिडी रोधी जांच की शुरुआत

फा.सं. 6/8/2018-डीजीएडी.—यतः आटोमोटिव टायर मेन्युफेक्चरर्स एसोशिएशन (जिसे आगे एटीएमए या याचिकाकर्ता/याचिकाकर्ता एसोशिएशन कहा गया है) ने घरेलू उत्पादकों अर्थात् अपोलो टायर्स लि., जे.के. टायर इंडस्ट्रीज लि., एमआरएफ लि. और सिएट लि. की ओर से समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (सब्सिडीप्राप्त वस्तुओं की पहचान, उन पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें चीन जनवादी गणराज्य (जिसे आगे संबद्ध देश कहा गया है) से बसों या लारियों में प्रयोग किए जाने वाले प्रकार के रबड़ के न्यू न्यूमेटिक टायरों, (जिसे आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है) पर सब्सिडी का आरोप लगाया है और संबद्ध देश के मूल की संबद्ध वस्तु के आयातों पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने के लिए सब्सिडीरोधी जांच की शुरुआत करने का अनुरोध किया है।

क. सब्सिडीकरण का आरोप

2. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि चीन जनवादी गणराज्य में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों/निर्यातकों को विभिन्न प्रदेशों की सरकारों और नगरपालिकाओं जिनमें उत्पादक/निर्यातक स्थित हैं और अन्य सार्वजनिक निकायों सहित चीन सरकार में विभिन्न स्तरों द्वारा प्रदत्त कार्रवाई योग्य सब्सिडीयों से लाभ मिल रहा है। याचिकाकर्ता ने सार्वजनिक डोमेन में यथा उपलब्ध संगत कानूनों, नियमों और विनियमों और संगत सरकारी एजेंसियों और लोक निकायों की अधिसूचनाओं और अन्य जांचकर्ता प्राधिकारियों जिन्होंने ऐसी स्कीमों की विस्तृत जांच की है और प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी कार्यक्रम की मौजूदगी निर्धारित की है, पर भरोसा किया है।

ख. परामर्श

3. एएससीएम के अनुच्छेद 13 के अनुसार चीन जनवादी गणराज्य की सरकार के प्रतिनिधियों के साथ नई दिल्ली में 20 मार्च, 2018 को जॉच पूर्व परामर्श किया गया था। चीन जनवादी गणराज्य की सरकार के प्रतिनिधियों की टिप्पणियों को रिकार्ड में लिया गया है।

ग. सब्सिडी कार्यक्रम

4. याचिकाकर्ता द्वारा प्रदत्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य से पता चलता है कि चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों और निर्यातकों को चीन जन. गण. की सरकार और/या अन्य सार्वजनिक निकायों द्वारा प्रदत्त नीचे यथा सूचीबद्ध अनेक सब्सिडियों से लाभ मिला है। कथित सब्सिडियों में निधियों का सीधे हस्तांतरण शामिल है जैसे अनुदान अधिमान्य ऋण और इक्विटी निवेश : सरकार या सार्वजनिक निकाय द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का कम मूल्य पर प्रावधान सरकार या सार्वजनिक निकाय द्वारा छोड़ा गया राजस्व जैसे कर प्रोत्साहन आदि।

I. अनुदान के रूप में लाभ प्रदान करने वाले कार्यक्रम/स्कीमें**I. अनुदान के रूप में अभिज्ञात कार्यक्रम**

कार्यक्रम 1: प्रसिद्ध ब्रांड्स कार्यक्रम

कार्यक्रम 2: ऊर्जा बचाने वाले प्रौद्योगिकी सुधार के लिए विशेष निधि

कार्यक्रम 3: स्वच्छ उत्पादन प्रौद्योगिकी निधि

कार्यक्रम 4: राज्य प्रमुख प्रौद्योगिकी नवीनीकरण परियोजनाएं निधि

कार्यक्रम 5: फिक्स्ड एसेट इनवेस्टमेंट सब्सिडी

कार्यक्रम 6: हाइटेक इंडस्ट्री के वेंचर इन्वेस्टमेंट फंड

कार्यक्रम 7: विदेशी निवेश के साथ मुख्यालय और क्षेत्रीय मुख्यालय की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान

कार्यक्रम 8: अभिनव लघु और मझौले उद्यम अनुदान

कार्यक्रम 9: स्थानीय सरकारों द्वारा पाटनरोधी और / या प्रतिसंतुलनकारी कानूनी व्यय की प्रतिपूर्ति

प्रोग्राम 10: सुपरस्टार एंटरप्राइज़ अनुदान

कार्यक्रम 11: निर्यात सहायता अनुदान

कार्यक्रम 12: अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) सहायता अनुदान

कार्यक्रम 13: हेफेई आर्थिक और प्रौद्योगिकी विकास क्षेत्र में स्थित कंपनियों के लिए सब्सिडी

कार्यक्रम 14: विदेशी निवेश उद्यमों के लिए अन्हुई प्रांत सब्सिडीज

कार्यक्रम 15: हेफेई नगर निगम निर्यात संवर्धन नीतियां

कार्यक्रम 16: कुंशन आर्थिक और तकनीकी विकास क्षेत्र में स्थित कंपनियों के लिए सब्सिडी

कार्यक्रम 17: ऑटोमोबाइल और टायर इंडस्ट्रीज के लिए वैहेई नगर पालिका सब्सिडी

कार्यक्रम 18: रोंगचेंग आर्थिक विकास क्षेत्र में स्थित कंपनियों के लिए सब्सिडीज

कार्यक्रम 19: ग्वांगडोंग और झेजियांग प्रांत में स्थित उद्यमों के लिए निर्यात ब्याज सब्सिडी निधि

कार्यक्रम 20: गुआंगडोंग प्रांत में उद्योगों के "बाह्य विस्तार" के लिए निधि

कार्यक्रम 21: आयोलस के लिए प्रत्यक्ष सरकारी अनुदान

कार्यक्रम 22: डबल काइन के लिए प्रत्यक्ष सरकारी अनुदान

कार्यक्रम 23: जीआईटीआई को प्रत्यक्ष सरकारी अनुदान

कार्यक्रम 24: गुइंझू टायर के लिए प्रत्यक्ष सरकारी अनुदान

कार्यक्रम 25: क्लिंगदाओ डबल स्टार को प्रत्यक्ष सरकारी अनुदान

कार्यक्रम 26: सैलून समूह को प्रत्यक्ष सरकारी अनुदान

II. चीन में कर प्रोत्साहनों के रूप में अभिज्ञात कार्यक्रम

कार्यक्रम 27: अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) खर्चों की कटौती के लिए कर नीतियां

कार्यक्रम 28 - एफआईई के अनुसंधान और विकास के लिए अधिमान्य टैक्स नीतियां

कार्यक्रम 29: एफआईई द्वारा अनुसंधान और विकास के लिए कर प्रतिपूर्ति

- कार्यक्रम 30: घरेलू उत्पादित और निर्मित उत्पादन उपकरणों की खरीद के लिए आयकर क्रेडिट
- कार्यक्रम 31: कंपनियों जो उच्च और नई तकनीक कंपनियों के रूप में मान्यता प्राप्त हैं के लिए अधिमान्य कर नीति/आयकर कटौती
- कार्यक्रम 32: व्यापक संसाधन उपयोग (विशेष कच्चे माल) में लगे उद्यमों के लिए आयकर रियायतें
- कार्यक्रम 33: विशेष उपकरणों की खरीद से संबंधित टैक्स क्रेडिट
- कार्यक्रम 34: चीन में बनाये गए उपकरण खरीदने के लिए घरेलू स्वामित्व वाली कंपनियों के लिए आयकर क्रेडिट
- कार्यक्रम 35: आयातित प्रौद्योगिकियों और उपकरणों के लिए टैरिफ और वैट छूट
- कार्यक्रम 36: चीनी निर्मित उपकरणों की खरीद पर घरेलू फर्मों के लिए वैट धन-वापसी
- कार्यक्रम 37: केंद्रीय क्षेत्र के लिए वैट छूट और कटौती
- कार्यक्रम 38: उत्पादक एफआईआई के लिए निर्धारित कर दर को 10 साल से कम अवधि तक नहीं चलाने के लिए निर्धारित किया गया है
- कार्यक्रम 39- विदेशी निवेश निर्यात उद्यमों के लिए अधिमान्य टैक्स नीतियां
- कार्यक्रम 40- एफआईआई के लिए अधिमान्य टैक्स नीतियां जो कि प्रौद्योगिकी गहन और ज्ञान गहन हैं
- कार्यक्रम 41- एफआईआई और विदेशी उद्यमों के लिए अधिमान्य टैक्स नीतियां जिनके चीन में प्रतिष्ठान या स्थान हैं और घरेलू उत्पादित उत्पाद खरीदने में उत्पादन या व्यापार संचालन में लगे हैं
- कार्यक्रम 42- विदेशी निवेशकों द्वारा एफआईआई मुनाफे के पुनर्निवेश के लिए आयकर वापसी
- कार्यक्रम 43 - उन्नत प्रौद्योगिकी एफआईआई के लिए आयकर में कटौती
- कार्यक्रम 44: विशेष आर्थिक क्षेत्रों (शंघाई पुडोंग क्षेत्र को छोड़कर) में स्थापित विदेशी निवेश एफआईआई के साथ उद्यमों के लिए अधिमान्य टैक्स नीतियां)
- कार्यक्रम 45: तटीय आर्थिक ओपन क्षेत्रों और आर्थिक और तकनीकी विकास क्षेत्रों में स्थापित एफआईआई के लिए अधिमान्य टैक्स नीतियां
- कार्यक्रम 46: एसईजेड और अन्य नामित क्षेत्रों में स्थानीय आयकर छूट और/या कमी
- कार्यक्रम 47: एसईजेड और अन्य नामित क्षेत्रों में कॉर्पोरेट आयकर छूट और/या कमी
- कार्यक्रम 48: एसईजेड और अन्य नामित क्षेत्रों में आयातित सामग्रियों और उपकरणों पर टैरिफ और मूल्य-वर्धित कर (वैट) छूट
- कार्यक्रम 49: पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्यमों के लिए अधिमान्य आयकर नीति
- कार्यक्रम 50: केन्द्रीय और पश्चिमी क्षेत्रों के लिए कर रियायतें

III. अधिमान्य ऋण और ऋण के रूप में अभिज्ञात कार्यक्रम

- कार्यक्रम 51: सरकारी नीति ऋण
- कार्यक्रम 52: एसओई के लिए अधिमान्य ऋण
- कार्यक्रम 53: निर्यात-उन्मुख उद्यमों और निर्यात ऋण ब्याज सब्सिडी के लिए रियायती ऋण
- कार्यक्रम 54- टायर उद्योग के लिए अधिमान्य ऋण और ब्याज दरें

IV. निर्यात वित्तपोषण और निर्यात ऋण के रूप में अभिज्ञात कार्यक्रम

- कार्यक्रम 55: निर्यात विक्रेता को ऋण
- कार्यक्रम 56: निर्यात क्रेता ऋण
- कार्यक्रम 57: राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों से अन्य निर्यात वित्तपोषण
- कार्यक्रम 58: निर्यात क्रेडिट बीमा सब्सिडी
- कार्यक्रम 59: निर्यात क्रेडिट गारंटी

V. इक्विटी के रूप में अभिज्ञात कार्यक्रम

- कार्यक्रम 60- इक्विटी निवेश
- कार्यक्रम 61- अवैतनिक लाभांश
- कार्यक्रम 62- योग्य निवासी उद्यमों के बीच लाभांश छूट

VI. माल और सेवाओं के प्रावधान के रूप में अभिज्ञात कार्यक्रम

- कार्यक्रम 63: पर्याप्त मूल्य से कम पर बिजली की व्यवस्था
 कार्यक्रम 64: पर्याप्त मूल्य से कम पर पानी की व्यवस्था
 कार्यक्रम 65: औद्योगिक और अन्य विशेष आर्थिक क्षेत्र में भूमि उपयोग अधिकार
 कार्यक्रम 66: एसओई के लिए भूमि उपयोग अधिकार
 कार्यक्रम 67 - एफआईई के लिए भूमि उपयोग अधिकार
 कार्यक्रम 68: पर्याप्त मूल्य से कम पर कार्बन ब्लैक की व्यवस्था
 कार्यक्रम 69: पर्याप्त मूल्य से कम पर नायलॉन कॉर्ड की व्यवस्था
 कार्यक्रम 70: पर्याप्त मूल्य से कम पर सिंथेटिक रबड़ और बुटैडिनी की व्यवस्था
 कार्यक्रम 71 - पर्याप्त मूल्य से कम पर प्राकृतिक रबड़ की व्यवस्था
 कार्यक्रम 72 - पर्याप्त मूल्य से अधिक पर सरकार द्वारा माल की खरीद

5. यह आरोप लगाया गया है कि उपरोक्त योजनाएं सब्सिडी हैं क्योंकि उनमें चीन जनवादी गणराज्य सरकार या अन्य क्षेत्रीय या स्थानीय सरकारों से सार्वजनिक निकायों से वित्तीय अंशदान शामिल हैं और प्राप्तकर्ता(ओं) को लाभ प्रदान करते हैं। उनके आयातित वस्तुओं के मुकाबले घरेलू वस्तुओं के प्रयोग से जुड़े और/या निर्यात प्रदर्शन से जुड़े और/या कुछ उद्यमों या उद्यमों के समूह और/या उत्पादों और/या क्षेत्रों तक सीमित घरेलू वस्तुओं के उपयोग से जुड़े होने का भी आरोप है और इसलिए ये विशिष्ट और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क योग्य हैं।

6. निर्दिष्ट प्राधिकारी अन्य सब्सिडी की जांच करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं, जिन्हें जांच की प्रक्रिया के दौरान संबद्ध वस्तु के उत्पादकों और निर्यातकों के लिए उपलब्ध और मौजूद पाया जाता है।

ग. क्षति और कारणात्मक संबंध का आरोप

7. याचिकाकर्ता ने जो नियमों के अनुसार निर्धारित घरेलू उद्योग को 'क्षति' से संबंधित विभिन्न मानदंडों के बारे में जानकारी दी है। याचिकाकर्ता द्वारा प्रदत्त साक्ष्य से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि संबद्ध देश से आधार वर्ष की तुलना में क्षति अवधि के दौरान आयात केवल न केवल समग्र रूप से बढ़ा है, बल्कि भारत में उत्पादन और खपत की दृष्टि से भी उसमें वृद्धि हुई है, और आयात की कीमतों में काफी गिरावट आई है। कथित सब्सिडी वाले आयातों से कीमतों में गिरावट आई है, जिससे घरेलू उद्योग के लाभ में गिरावट आई है। अप्रयुक्त क्षमता, लाभ, निवेश पर आय, नकदी प्रवाह और मालसूची में भारी वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग का कार्यनिष्पादन विकृत हो गया है। प्राधिकरण ने नोट किया है कि इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि घरेलू उद्योग को 'क्षति' चीन जनवादी गणराज्य से सब्सिडीप्राप्त आयात के कारण हुआ है।

ड. जाँच की शुरुआत

8. प्राधिकारी पाते हैं कि चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तु के उत्पादन या निर्यात पर पर्याप्त प्रतिसंतुलन योग्य सब्सिडी की मौजूदगी का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है और इस तरह के सब्सिडीप्राप्त आयात घरेलू उद्योग को उसकी मात्रा और मूल्य प्रभाव के माध्यम से वास्तविक क्षति का कारण बन रहे हैं।

9. उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए, प्राधिकारी नियमावली के नियम 6 के अनुसार कथित सब्सिडी और घरेलू उद्योग को परिणामी वास्तविक क्षति वास्तविक क्षति की जांच की शुरुआत करते हैं, ताकि कथित सब्सिडी की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

च. घरेलू उद्योग

10. यह आवेदन ऑटोमोटिव टायर मेन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन (जिसे "एटीएमए" कहा गया है) द्वारा अपोलो टायर्स लिमिटेड, जे.के. टायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एमआरएफ लिमिटेड और सीएट लिमिटेड की ओर से दायर किया गया है। रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, आवेदक का उत्पादन, भारतीय उत्पादन के 50% से अधिक होने के कारण उसका कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है। इसलिए प्राधिकारी, यह निर्धारित करते हैं कि मौजूदा आवेदन में घटक घरेलू उत्पादक अर्थात् अपोलो टायर्स लिमिटेड, जेके टायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एमआरएफ लिमिटेड और सीएट लिमिटेड ने नियम 2 (घ) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है और आवेदन संबंधित नियमावली के नियम 6 (3) के संदर्भ में योग्यता संबंधी मापदंड को पूरा करता है।

छ. विचाराधीन उत्पाद

11. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद " बसों या लारियों में प्रयोग किए जाने वाले न्यू न्यूमेटिक टायर, हैं जो सीमाशुल्क उपशीर्ष 4011.20 के तहत वर्गीकृत किए जा सकते हैं।

ज. समान वस्तु

12. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु, चीन जनवादी गणराज्य के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के समान वस्तु हैं। यह बताया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और चीन जनवादी गणराज्य से निर्यातित वस्तु के बीच कोई खास अंतर नहीं है। याचिकाकर्ता का दावा है कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को चीन जन. गण. से आयातित संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

झ. शामिल देश

13. वर्तमान जांच में शामिल देश चीन जनवादी गणराज्य (जिसे चीन जन. गण. भी कहा गया है) है।

ञ. जांच अवधि

14. वर्तमान जांच में जांच की अवधि (पीओआई) अक्टूबर, 2016 से 30 सितंबर, 2017 (12 महीने) की है। क्षति जांच अवधि में 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 और जांच अवधि शामिल है।

ट. प्रक्रिया और सूचना प्रस्तुत करना

15. चीन जनवादी गणराज्य में निर्यातकों, चीन जन. गण. की सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों व प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से लिखा जा रहा है। वर्तमान जांच में भाग लेने का इच्छुक कोई पक्षकार निम्नलिखित पते पर लिख सकता है :

निर्दिष्ट प्राधिकारी

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,

5 संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

16. संबंधित नियमावली के नियम 7(5) के अनुसार, निर्दिष्ट प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद के औद्योगिकी उत्पादकों और प्रतिनिधि उपभोक्ता संगठनों को भी सब्सिडी, क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में से संगत सूचना प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है।

(i) समय-सीमा

17. वर्तमान जांच संबंधित कोई सूचना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। तथापि चीन की सरकार, निर्यातक और आयातक जिन्हें अलग से लिखा गया है, को उन्हें अलग से प्रेषित पत्र की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर सूचना प्रस्तुत करना अपेक्षित है। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, रिकार्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं। यह नोट किया जाए कि समय-सीमा को बढ़ाने के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ii) गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

18. नियमावली के नियम 8 के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों के लिए प्राधिकारी को प्रदत्त किसी गोपनीय सूचना का अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और (ख). अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए और उनकी साफ्ट प्रतियां होनी चाहिए।

19. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां प्रस्तुत करना जरूरी होगा।

20. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए, सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशकरण क्यों संभव नहीं है।
21. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध / रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।
22. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
23. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

(iii) असहयोग

24. नियम 7(8) के अनुसार, यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

(iv) सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

25. नियम 7(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

(v) असहयोग

26. इस कार्यवाही में शामिल चीन जन. गण. में निर्यातक उत्पादकों की संभावित रूप से बड़ी संख्या को देखते हुए और निर्धारित समय-सीमा के भीतर जाँच को पूरा करने के लिए, प्राधिकारी प्रतिदर्श का चयन करके जाँच के लिए तर्कसंगत संख्या में निर्यातक उत्पादकों को सीमित कर सकते हैं। नियमावली के नियम 17(3) के अनुसार यदि अपेक्षित हो तो प्रतिदर्श लिया जाएगा।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2018

Subject: Initiation of Countervailing Duty/Anti-subsidy investigation concerning imports of New Pneumatic Tyres for Buses and Lorries from People's Republic of China.

F. No. 6/8/2018-DGAD.—Whereas Automotive Tyre Manufacturer's Association (hereinafter referred to as "ATMA" or Petitioner/Petitioner Association) has filed an application on behalf of domestic producers namely Apollo Tyres Ltd., J. K. Tyre Industries Ltd., MRF Ltd. and Ceat Ltd., before the Designated Authority, in accordance with the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, (hereinafter referred to as the Rules), alleging subsidization of New Pneumatic Tyres for Buses and Lorries (hereinafter referred to as the subject goods), from People's Republic of China (hereinafter referred to as the subject country) and requested for initiation of an anti-subsidy investigation for levy of countervailing duties on the imports of the subject goods, originating in the subject country.

A. Allegation of subsidization

2. The petitioner has alleged that the producers/exporters of the subject goods in People's Republic of China have benefited from the actionable subsidies provided by various levels in the Government of China, including the Governments of the different Provinces and Municipalities in which the producers/exporters are located, and

other 'Public Bodies'. The petitioner has relied upon the relevant Laws, Rules and Regulations and other Notification of the relevant Government Agencies and Public Bodies as available in the public domain and in determinations of other investigating Authorities who have conducted comprehensive investigation of such schemes and concluded existence of countervailable subsidy programs.

B. Consultation

3. In terms of Article 13 of ASCM pre-initiation consultations were held with the representatives of the Government of the People's Republic of China on 20th March, 2018 in New Delhi. The comments of representatives of the Govt. of People's Republic of China have been taken on record.

C. Subsidy Programs

4. The prima facie evidence provided by the petitioner shows that the producers and exporters of the subject goods in the People's Republic of China have benefited from a number of subsidies, as listed below, granted by the Government of People's Republic of China and/or other public bodies. The alleged subsidies consist of direct transfer of funds such as grants, preferential loans and equity infusion ; provision of goods and services by the Government or Public body for less than adequate remuneration; Revenue foregone by the Government or Public body such as Tax Incentives etc.

I. Programs/scheme providing benefits in the form of Grant

I. Identified Programs in the form of Grants:

Program 1: Famous Brands Program

Program 2: Special Fund for Energy-Saving Technology Reform

Program 3: The Clean Production Technology Fund

Program 4: The State Key Technology Renovation Projects Fund

Program 5: Fixed Asset Investment Subsidies

Program 6: Venture Investment Fund of Hi-Tech Industry

Program 7: Grants for Encouraging the Establishment of Headquarters and Regional Headquarters with Foreign Investment

Program 8: Innovative Small and Medium Enterprise Grants

Program 9: Reimbursement of Anti-dumping and/or Countervailing Legal Expenses by the Local Governments

Program 10: Superstar Enterprise Grant

Program 11: Export Assistance Grant

Program 12: Research & Development (R&D) Assistance Grant

Program 13: Subsidies for Companies Located in the Hefei Economic and Technology Development Zone

Program 14: Anhui Province Subsidies for Foreign-Invested Enterprises

Program 15: Hefei Municipal Export Promotion Policies

Program 16: Subsidies for Companies Located in the Kunshan Economic and Technological Development Zone

Program 17: Weihai Municipality Subsidies for the Automobile and Tyre Industries

Program 18: Subsidies for Companies Located in the Rongcheng Economic Development Zone

Program 19: Export Interest Subsidy Funds for Enterprises Located in Guangdong and Zhejiang Provinces

Program 20: Funds for "Outward Expansion" of Industries in Guangdong Province

Program 21: Direct Government Grants to Aeolus

Program 22: Direct Government Grants to Double Coin

Program 23: Direct Government Grants to GITI

Program 24: Direct Government Grants to Guizhou Tyre

Program 25: Direct Government Grants to Qingdao Double Star

Program 26: Direct Government Grants to Sailun Group

II. Identified Programs in the Form of Tax Incentives in China

Program 27: Tax Policies for the deduction of research and development (R&D) expenses

Program 28 - Preferential Tax Policies for the Research and Development of FIEs

Program 29: Tax Offsets for Research and Development by FIEs

Program 30: Income tax credit for the purchase of domestically Produced & manufactured production equipment

Program 31: Preferential tax policies/ Income Tax Reductions for companies that are recognized as high and new technology companies

Program 32: Income tax concessions for the enterprises engaged in comprehensive resource utilization (special raw materials')

Program 33: Tax credit concerning the purchase of special equipment

Program 34: Income Tax credits for domestically owned Companies Purchasing Chinese made Equipment

Program 35: Tariff and VAT exemptions for imported Technologies and equipment

Program 36: VAT Refunds for domestic firms on Purchases of Chinese made Equipment

Program 37: VAT Exemptions and Deductions for central regions

Program 38: Reduced Tax Rate for productive FIEs scheduled to operate for a period not less Than 10 Years

Program 39- Preferential Tax policies for Foreign Invested Export Enterprises

Program 40- Preferential Tax policies for FIEs which are technology intensive and knowledge intensive

Program 41- Preferential Tax Policies for FIEs and Foreign Enterprises which have establishments or places in China and are engaged in production or business operations purchasing domestically produced equipments

Program 42- Income Tax refund for re-investment of FIE Profits by Foreign Investors

Program 43 - Income Tax reduction for Advanced Technology FIEs

Program 44: Preferential Tax policies for enterprises with Foreign Investment FIEs) established in Special Economic Zones (excluding Shanghai Pudong area)

Program 45: Preferential Tax policies for FIEs established in the Coastal Economic open areas and in the Economic and Technological Development Zones

Program 46: Local Income Tax exemption and/or Reduction in SEZs and other designated areas

Program 47: Corporate Income Tax exemption and/or reduction in SEZs and other designated areas

Program 48: Tariff and Value-added Tax (VAT) exemptions on imported materials and equipment in SEZs and other designated areas

Program 49: Preferential income tax policy for the enterprises in the Northeast region

Program 50: Tax concessions for Central and Western regions

III. Identified Programs in the Form of Preferential Loans & Lending

Program 51: Government policy lending

Program 52: Preferential loans to SOE

Program 53: Discounted Loans for Export-Oriented Enterprises and Export loan interest subsidies

Program 54- Preferential loans and interest rates to the Tyre Industry

IV. Identified Programs in the Form of Export Financing and Export Credit

Program 55: Export seller's credit

Program 56: Export buyer's credit

Program 57: Other export financing from State-Owned Banks

Program 58: Export credit insurance subsidies

Program 59: Export credit guarantees

V. Identified Programs in the Form of Equity

Program 60- Equity infusions

Program 61- Unpaid dividends

Program 62- Dividend exemption between qualified resident enterprises

VI. Identified Programs in the Form of Provision of Goods and Services

Program 63: Provision of electricity for less than adequate remuneration

Program 64: Provision of water for less than adequate remuneration

Program 65: Land Use rights in industrial and other Special Economic Zone

Program 66: Land Use rights for SOEs

Program 67- Land Use rights for FIEs

Program 68: Provision of Carbon Black for less than adequate remuneration

Program 69: Provision of Nylon Cord for less than adequate remuneration

Program 70: Provision of Synthetic Rubber and Butadiene for Less Than Adequate Remuneration

Program 71 - Provision of Natural Rubber for less than adequate remuneration

Program 72 - Purchase of goods by the Government for higher than adequate Remuneration

5. It has been alleged that the above schemes are subsidies since they involve a financial contribution from the Government of the People's Republic of China or other regional or local governments, including public bodies, and confer benefit to the recipient(s). They are also alleged to be contingent upon the use of domestic over imported goods and/or contingent upon export performance and/or limited to certain enterprises or groups of enterprises and/or products and/or regions, and therefore, specific and countervailable.

6. The Designated Authority reserves the right to investigate other subsidies, which may be found to exist and availed by the producers and exporters of the subject goods, during the course of the investigation.

D. Allegation of Injury and Causal Link

7. The petitioner has furnished information on various parameters relating to 'injury' to the domestic industry as prescribed under Rules. The evidence provided by the petitioner *prima facie* shows that the imports from subject country during the injury period have increased as compared to base year, not only in absolute terms, but also in relation to production and consumption in India,. Alleged subsidized imports appear to have caused price depression leading to decline in profits for the domestic industry. Performance of the domestic industry has deteriorated in terms of profits, return on investments, cash flow. The Authority notes that there is *prima facie* evidence that the 'injury' to the domestic industry has been caused by subsidized imports from People's Republic of China.

E. Initiation of the Investigation

8. The Authority finds that there is *prima facie* evidence of existence of countervailable subsidies on production and export of the subject goods in People's Republic of China and such subsidized imports are causing material injury to the domestic industry through their volume and price effects.

9. In view of the above position, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged subsidization and consequent material injury to the domestic industry in terms of the Rule 6 of the Rules supra, to determine the existence, degree and effect of alleged subsidization and to recommend the amount of countervailing duty, which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

F. Domestic Industry

10. The application has been filed by the Automotive Tyre Manufacturer's Association (referred to as "ATMA") on behalf of Apollo Tyres Ltd., J. K. Tyre Industries Ltd., MRF Ltd. and Ceat Ltd., As per the evidence available on record, production of the petitioner, being more than 50% of Indian production, accounts for a major proportion of the total domestic production. The Authority, therefore, determines that the constituent domestic producers in the present application namely Apollo Tyres Ltd., J. K. Tyre Industries Ltd., MRF Ltd. and Ceat Ltd constitute the domestic industry within the meaning of Rule 2 (b) and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 6 (3) of the Rules supra.

G. Product under consideration

11. The product under consideration in the present investigation is "New Pneumatic Tyres for Buses and Lorries", classifiable under Customs Sub-heading 4011.20.

H. Like Articles

12. The petitioner has claimed that the goods produced by the domestic industry are like articles to the subject goods originating in or exported from People's Republic of China. It has been stated that there is no significant difference in the subject goods produced by the petitioner and those exported from People's Republic of China. The petitioner claims that the two are technically and commercially substitutable. For the purpose of present investigation, the subject goods produced by the domestic industry are being treated as 'like articles' of the subject goods imported from People's Republic of China.

I. Country involved

13. The country involved in the present investigation is People's Republic of China.

J. Period of investigation

14. The Period of Investigation (POI) in the present investigation is October 2016-September, 2017 (12 months). The injury investigation period shall cover the periods 2014-15, 2015-16, 2016-17 and the period of investigation.

K. Procedure & Submission of information

15. The exporters in the People's Republic of China, Government of the People's Republic of China, importers and users in India known to be concerned with the product and the domestic industry are being informed separately to enable them to provide all information relevant in the form and manner prescribed. Any other party interested to participate in the present investigation may also write to:

The Designated Authority
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties
Department of Commerce
Ministry of Commerce & Industry
4th Floor, Jeevan Tara Building,
5, Parliament Street, New Delhi – 110011

16. As per Rule 7(5) of the Rules supra, the Designated Authority is also providing opportunity to the industrial users of the product under investigation, and to representative consumer organizations who can furnish information which is relevant to the investigation regarding subsidy, injury and causal link. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation within the time limit set out below.

(i) Time limit

17. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than 40 (forty) days from the date of publication of this notification. The Government of China, known exporters and importers, who are being addressed separately, are however required to submit the information within 40 (forty) days from the date of the letter addressed to them separately. If no information is received within the prescribed time limit or the submitted information is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules. It may be noted that no request, whatsoever, shall be entertained for extension in the prescribed time limit.

(ii) Submission of Information on Non-Confidential basis

18. In terms of Rule 8 of the Rules, the interested parties are required to submit non-confidential version of any confidential information provided to the Authority. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

19. Information supplied without any mark as "Confidential" shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies each of the confidential version and the non-confidential version must be submitted.

20. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

21. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked / summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary; a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

22. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

23. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied

and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such confidential information.

(iii) Non cooperation

24. In terms of Rule 7(8), in case where an interested party refuses access to or does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

(iv) Inspection of Public File

25. In terms of Rule 7(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

(v) Sampling

26. In view of the possibility of participation by large number of exporter(s)/producer(s) in the People's Republic of China involved in this proceeding and the limited time period for completion of the investigation, the Authority may limit the exporter(s)/producer(s) to be investigated to a reasonable number by selecting a sample. The sampling shall be carried out, if required, in terms of Rule 17(3) of the Rules.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Designated Authority